भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 1919
17.03.2025 को उत्तर देने के लिए

2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के प्रयास

1919 **श्रीमती संगीता यादवः**

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सांख्यिकी, सर्वेक्षणों और योजना कार्यान्वयन के माध्यम से वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनके संभावित योगदान के आधार पर नई नीतियों/योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली के क्षेत्र में अनेक पहल की हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने की पहल के एक हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर गुणवत्ता वाले आंकड़ों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधार किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डेटा संग्रह, डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रसार और डेटा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है। कुछ पहल इस प्रकार हैं:

(i) सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों पर विकास का आकलन करने और साक्ष्य आधारित प्रयासों का समर्थन करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने पूरे भारत में, राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार आदि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित किए हैं।

(ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समय अंतराल को कम करने हेतु डेटा संग्रह के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में अंतर्निहित सत्यापन तंत्र के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

(iii) प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों, जैसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुमान न्यूनतम समय अंतराल के साथ अग्रिम रिलीज कैलेंडर (एआरसी) के अनुसार जारी किए जाते हैं।

(iv) सरकारी सांख्यिकी हेतु डेटा प्रबंधन को आसान बनाने के लिए, ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल महत्वपूर्ण मैक्रो संकेतकों का समय श्रृंखला डेटा और मंत्रालय की प्रमुख डेटा परिसंपत्तियों की सूची प्रदान करता है।

(v) राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में चल रही केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग (एसएसएस) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की गई।

यद्यपि मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से नई नीतियों/योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, फिर भी मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न आंकड़े 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन प्रदान करते हैं।

*****